

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के रोकथाम के लिए बनाएं गए संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान

राहुल कुमार यादव
पी0 एच0 डी0 (शोध छात्र)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
लखनऊ, उत्तर प्रदेश
Email.Id-rksunny1989@gmail.com
Mobile No-9044740286

प्रस्तावना:—

स्त्री और पुरुष प्रकृति के अभिन्न अंग हैं तथा इनमें से किसी एक के अभाव में न तो सृष्टि की रचना की जा सकती है और न ही मानव के विकास की कल्पना की जा सकती है। ऋग्वैदिक काल को छोड़ कर बाकी किसी काल में नारी की स्थिति अच्छी नहीं रही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है— **ढोल गंवार शूद्र पशु नारी।**

ये सब ताड़न के अधिकारी।।

उपरोक्त पंक्ति से पता चलता है कि तुलसीदास जी ने नारी को पशु के समान माना है तथा कहा है कि उनके साथ शूद्र और ढोल जैसे व्यवहार करना चाहिए।

साधारण रूप से अनुसूचित जाति या दलित जाति का तात्पर्य अस्पृश्यता से है। आर्थात् ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार जिनका स्पर्श करना वर्जित है या जिनके स्पर्श मात्र से दूसरों की पवित्रता नष्ट हो जाए तथा इनके लिए अछूत शब्द का भी प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ है जो छूने योग्य न हो, (रावत, ज्ञानेन्द्र और डॉ0 मंजू, सुमन, 2004)।

भारत में दलित महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये पुरे संसार में हर जगह समुह से पृथक या हाशिएं पर रखी गयी है तथा ये पुरे संसार की आबादी का 2 प्रतिशत हिस्सा है। (डॉ0 कुमारी आर0 सान्था, 2016)

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार— भारत में कुल दलित महिला की आबादी 5,18,71,211 तथा प्रतिशत में कुल आबादी का 8.8 प्रतिशत है। तथा ग्रामीण आबादी 4,66,92,821 तथा प्रतिशत में 11.5 तथा शहरी आबादी 51,78,390 है जो कि प्रतिशत में 2.9 प्रतिशत है।(भारतीय जनगणना, 2011)

दलित महिलाएं तीन रूपों से हिंसा की शिकार होती हैं, प्रथम गरीबी के कारण द्वितीय महिला होने के कारण तृतीय दलित जाति से संबंधित होने के कारण। प्रथागत निषेधों का दलित महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से पालन करना पड़ता है। दलित महिलाओं पर न केवल उच्च जाति के पुरुष और

महिलाएँ हिंसा करती हैं अपितु दलित समुदाय के पुरुषों द्वारा भी उन पर अत्याचार किया जाता है, (डॉ०, कुमारी, आर०, सान्था, 2016)।

भारत के श्रम बाजारों में जाति और लिंग के प्रतिच्छेदन के आधार पर समान समानताएं देखी जा सकती हैं। पवित्रता और प्रदूषण की पारंपरिक धारणा के कारण दलित महिलाओं के श्रम बाजार के अनुभव उच्च जातियों के महिलाओं से भिन्न हैं। दलित महिलाओं को शायद ही कभी उच्च जाति के घरों में खाना पकाने के लिए नियोजित किया जाता है। उन्हें घरों और सड़क की सफाई, कपड़े धोने और कभी-कभी बीमारों की देखरेख का काम करने के लिए काम पर रखा जाता है तथा अन्य जातियों के सम्पर्क में आने पर उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। अस्पृश्यता की यह धारणा उन्हें रोजगार में शारीरिक अलगाव और प्रतिबंध की ओर ले जाती है, (साधना. निधि, सोभरवाल, सोनालकर. वंदना—जुलाई 2015 पेज न. 6)।

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा:—

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2013 के अनुसार— भारत में प्रतिदिन चार दलित महिलाओं का बलात्कार किया जाता है तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2018 के अनुसार महिलाओं पर कुल 3,78,277 हिंसा हुईं जिनमें केवल 3,59,849 केस दर्ज किए गए। राज्यों में उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति हिंसा में शीर्ष स्थान पर है जहाँ 59,445 केस दर्ज किए गए तथा इसके पश्चात् क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

4 भारतीय राज्यों में 500 दलित महिलाओं के ऊपर हुए हिंसा के 3 साल के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश दलित महिलाएं एक या एक से अधिक प्रकार की हिंसा की शिकार हैं, आकड़े बताते हैं कि 62.4% मौखिक हिंसा, 54.8% शारीरिक हमला, 46.8% यौन उत्पीड़न, 43% ने घरेलू हिंसा और 23.2% ने बलात्कार का सामना किया है। (माथुर, अंजली, रिंतु, सुरेखा और अंशु, 2016, पेज न०-04)

उद्देश्य:—

1. महिलाओं और विशेषकर दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का पता लगाना।
2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनी प्रावधानों की जाँच करना।

शोध विधि:— प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है तथा तथ्य संग्रह के लिए द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(4)—नागरिकों के किसी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करना।

अनुच्छेद 16(4)—नागरिकों के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करना, जिन्हें राज्य ऐसा वर्ग मानता है, जिसे राज्य के सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

अनुच्छेद 17—अस्पृश्यता का अन्त कर उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है।

अनुच्छेद 19—अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया गया तथा किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी प्रदान की गयी।

अनुच्छेद 25—हिंदूओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया गया।

अनुच्छेद 29(2)—राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

अनुच्छेद 46—राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्द्धन करना चाहिए तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए।

अनुच्छेद 330—लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद 332—राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद 334—पंचायत व स्थानिय निकायों में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 338—अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने की बात की गयी है जिसका कर्तव्य है कि वह संविधान के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें।

अनुच्छेद 339(1)—इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात् राष्ट्रपति महोदय एक आयोग की नियुक्ति करेंगे, जो उन्हें सुझाव देगा। इस प्रकार प्रथम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अप्रैल, 1960 में यू. एन. डेबर के नेतृत्व में किया गया, जिसे डेबर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

आयोग का गठन 2003 में श्री दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में किया गया। भारत में अनुसूचित जाति या अनुसूचितजन जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन मार्च, 1992 को किया गया।

अनुच्छेद 341—राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 146 एवं 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक्-पृथक् विभागों की स्थापना।

अनुसूची 5—इसमें अनुसूचित जाति का वर्णन है।

कानूनी प्रावधान:—

सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829—इस अधिनियम के बनने के पूर्व भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। हिंदूओं में पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् विधवा स्त्रियों को (यह प्रलोभन देके की पति के साथ चिता में मरने से स्वर्ग मिलेगा) पति के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा को समाप्त करने में राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के प्रयास से तत्कालिक ब्रिटिश गवर्नर जर्नल लार्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया जिससे इस कुप्रथा पर रोक लगी।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856— इस अधिनियम के बनने से पूर्व विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और न उन्हें मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार था ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के आर्य समाज के प्रयासों से तत्कालिक वायसराय लार्ड केनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया जिसके तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की छूट प्रदान की गयी।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929—हर विलास शारदा के प्रयासों से सन् 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, बाल विवाह रोकने के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी तथा इस आयु से निचे विवाह कराने पर अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस अधिनियम के पास होने के बावजूद भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन जारी रहा तथा बाल विवाह को रोकने में अधिक कारगर नहीं रहा। इस अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए सन् 1978 में इसे संशोधित किया गया। यह अधिनियम अब बाल विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978 के नाम से प्रचलित है। इस अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की गयी तथा लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गयी।

हिंदू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम,1937—इस अधिनियम में हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसके मृत पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया।

अलग रहने और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम,1946—इस अधिनियम में कुछ परिस्थितियों में पति से पृथक रहने पर भरण—पोषण का अधिकार दिया गया।

विशेष विवाह अधिनियम,1954—इस अधिनियम द्वारा भिन्न—भिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को परस्पर विवाह की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा विवाह के एक विवाह के स्वरूप को मान्यता प्रदान की गयी।

हिंदू विवाह अधिनियम—1955 इस अधिनियम में हिन्दू विवाह में प्रचलित सभी विधियों को मान्यता दी गयी तथा हिंदू धर्म में व्याप्त सभी जातियों के पुरुषों और स्त्रियों को विवाह और तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम—1955 (जिसे 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार अधिनियम—1976 तथा पुनः संशोधित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम—1989 नाम दिया गया।) का उद्देश्य दलितों के प्रति भेदभाव और घृणा से उपजे अपराधों और अत्याचारों को रोकना है, (साधना.निधि, सोभरवाल, सोनालकर. वंदना—जुलाई 2015 पेज न.4)।

स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम,1956—वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान हैं—

1. "कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले यौन—सम्बन्ध के लिए अपना शरीर अर्पित करती है, 'वेश्या' है तथा अपने शरीर का इस प्रकार यौन—सम्बन्ध के लिए अर्पण करना 'वेश्यावृत्ति' है"
2. वेश्यालयों में रहने वाला व्यक्ति (सन्तान को छोड़ कर) यदि वह 18 वर्ष से अधिक का है और वेश्या की आय पर आश्रित रहता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास अथवा 1000 रुपए का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।
3. वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 1 से 15 वर्ष तक का कारावास तथा 2 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, (गुप्ता, एम0, एल0 एवं शर्मा, डी0, डी0, 2019)।

धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005— इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है, जो पारिवारिक हिंसा या धरेलू हिंसा की शिकार हैं। इस कानून की धारा—3 में धरेलू हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है—प्रत्यस्थी का ऐसा

कार्य या लोप अथवा आचरण जो व्यक्ति महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन शरीर-मन को क्षति ग्रस्त करता है। इस प्रकार अधिनियम में पाँच प्रकार के दुर्व्यवहारों का उल्लेख किया गया है— शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, तथा आर्थिक दुर्व्यवहार।

इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट धरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम की धारा-18 से 23 तक विभिन्न आदेश जैसे-संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश, सन्तानों की अभिरक्षा का आदेश, प्रतिकार आदेश तथा एकपक्षीय आदेश जारी कर सकते हैं। संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेशों के उल्लंघन पर एक वर्ष तक के कारावास या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानतीय बनाया गया है, (शर्मा, जी0, एल0 -2015)।

विशाखा दिशा-निर्देश—विशाखा निर्देश की पृष्ठभूमि यह थी कि राजस्थान की समाज सेविका भवरी देवी ने 1994 में एक बालविवाह का विरोध किया था। जिसके कारण 1997 में भवरी देवी का सामूहिक बलात्कार किया गया। जिसे बाद विशाखा नामक सवयं सेवी संस्था तथा अन्य लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और इसी प्ररिपेक्ष्य में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार वाद (1997) में काम काजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसे विशाखा निर्देश कहते हैं। ये निर्देश निम्नलिखित हैं—

- केन्द्र और राज्य दानो मिलकर संयुक्त रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास करे।
- कार्य स्थल पर महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है।
- लोगो में जागरुकता फैलाने के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर उनका प्रकाशन और वितरण किया जाना चाहिए।
- यौन उत्पीड़न की जाँच के लिए शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है तथा इस समिति का अध्यक्ष किसी महिला तथा को साथ ही एस समिति में कम से कम आधी आबादी महिलाओं की होनी चाहिए।

अक्टूबर 2012 में विशाखा निर्देश को और विस्तृत करते हुए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन इस कानून में कृषि क्षेत्र में काम करने वाली और सेना में काम करने वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया।

कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013—इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी कार्य स्थलों पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—

इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में हर तरह के कार्य करने वाली तथा हर उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ अश्लील बातों, महिलाओं की रजामंदी के बगैर

उनसे निकटता बढ़ाने का प्रयास तथा उनके साथ अश्लील व्यवहार को यौन उत्पीड़न के दायरे में रखा गया है।

यौन उत्पीड़न से ग्रसित महिला की अगर मौत हो जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तथा ऐसे मामले में न्यूनतम 20 वर्ष की सजा निर्धारित की गयी है।(शर्मा,जी0,एल0-2015, पेज न0 436-437)।

भारतीय दण्ड संहिता एवं यौन उत्पीड़न

भारतीय दण्डसंहिता की धारा, 375—इसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है

भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 376—इसमें बलात्कार के लिए 7 वर्ष, 10 वर्ष, अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

भारतीय दण्डसंहिता की धारा, 509— के तहत किसी शारीरिक क्रियाकलाप, या अश्लील हरकत से स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर भी एक साल की सजा या फिर जुर्माना का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 314—इसके तहत किसी भी स्त्री से छेड़छाड़ करने पे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, (भारतीय दण्ड संहिता, 1860)।

निष्कर्ष:—यद्यपि दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान किए गए हैं तथा केन्द्र व राज्य स्तर पर भी महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने, आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी नीतियों व योजनाओं की शुरुआत की गयी है। इन सब के बावजूद भी आज भी दलित महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ती जा रही तथा उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों के आधार पे ज्ञात होता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा तथा विशेषकर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है, जिसके प्रमुख कारण—अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, व राजनैतिक कारक उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही साथ कानूनों का सही से लागू न करना, तथा महिलाओं को इन संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी का अभाव आदि प्रमुख कारण हैं।

सन्दर्भ सूची:—

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की अधिनियम सं0 45
2. शर्मा, जी0 एल0 (2015), सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. अहुजा, राम (2012), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर

4. गुप्ता एम0 एल0 एवं शर्मा डी0 डी0 (2019) समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. रावत,ज्ञानेन्द्र और सुमन, डॉ0, मंजु (2004),दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सांथा,डॉ0,आर0,कुमारी,(2016,वॉल्यूम-2,6),दलित वोमेन इन इण्डिया : अ केस स्टडी ऑफ देअर वॉयलेन्स एण्ड एक्जिस्टेन्स,
7. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2013 और 2018
8. भारतीय जनगणना, 2011
9. Mathur,Anjali, Surekha,Ritu And Anshu, Jan,2016, Spousal Violence And Dalit Women: Theoretical Underpinnings And Retrospection, Page No-4